# भारतीय जनता पार्टी

*(केंद्रीय कार्यालय)*
11 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001
**दूरभाष** : 233005700; **फैक्स** : 23005787

**<u>भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री प्रकाश जावडेकर द्वारा सोमवार, 29 जून, 2009 को जारी प्रेस वक्तव्य</u>**

आगामी दिनों मे विकसित देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में कृषि–सबसिडी, जलवायु परिवर्तन की स्थिति, फिसाइल मेटीरियल कट ऑफ ट्रीटी और सी टी बी टी के बारे में भारत पर अपनी पहले की स्थिति को बदलने के लिए और अधिक दबाव डाला जायेगा। ये सभी मुद्दे राष्ट्रीय महत्व के हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों पर सावधानी पूर्वक नजर रखेगी।

भाजपा की मांग है कि सरकार को कृषि सबसिडी कम करने के बारे मे अमेरिका से पड़ रहे दबाव के सामने नही झुकना चाहिए क्योंकि यह मुद्दा आम तौर पर पूरे देश के लिए और विशेषतया 13 करोड़ कृषि कर्म करने वाले किसानों के लिए बहुत ही महत्व का हैं। भारत ने जिस स्थिति पर ढृढ़ रहने का निर्णय किया है वह राष्ट्रीय हित पर आधारित है और इसको देशभर की सभी पार्टियों का अनुमोदन प्राप्त है क्योंकि इसके पीछे भारतीय किसानों का बचाव करने का आशय विद्यमान है। राजग शासनकाल के दौरान वणिज्य मंत्री के रूप में श्री अरूण जेटली इस बिन्दु पर अपनी सहमति जता चुके हैं। श्री कमलनाथ ने भी अपनी पार्टी के शासनकाल के दौरान विश्व मंच पर इसी स्थिति का समर्थन किया था। किन्तु विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में इस स्थिति को गति–अवरोध के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

यह विडम्बना है कि अमेरिका, जो अपने किसानों को भारी सबसिडी देता है, सामान स्तर जुटाए बिना भारतीय बाजार मे प्रवेश करने की खुली छूट चाहता है। इसके कारण भारतीय कृषि कार्य प्रतियोगिताहीन हो जाएगा और इससे भारतीय कृषि को क्षति पहुॅंचेगी। अमेरिका 8 बिलियन डॉलर तक सबसिडी प्रदान करता है और उसे बढ़ा कर 15 बिलियन डॉलर तक करना चाहता है। अमेरिका की स्थिति अस्वीकार्य है और अस्वीकार्य ही रहेगी। भारत सरकार अपनी पहले की सर्वानुमतिपरक स्थिति से हटती प्रतीत होती है। यदि सरकार इन दबावों के आगे झुक जाती है तो यह भारतीय किसानों के लिए एक स्थायी क्षति होगी।

भारतीय जनता पार्टी सरकार को चेताती है कि वह अपनी पहले की स्थिति पर मजबूती से टिकी रहे अन्यथा उसे किसानों के आक्रोश का सामना करना होगा।

जलवायु परिवर्तन और सी टी बी टी के बारे में भी देशभर की राजनीतिक पार्टियों की स्थिति में मतैक्य बना हुआ है। संसार के विकसित देश प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के बारे मे भारतीय स्थिति का अनुमोदन नहीं करते हैं और वास्तविक धन की व्यवस्था किए बिना तथा अपनी ओर से उत्सर्जन में कमी करने की प्रतिबद्धता व्यक्त किये बिना भारत के उत्सर्जन में तत्काल कमी लाना चाहते हैं

**(श्याम जाजू)**
*मुख्यालय प्रभारी*